राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का परिचय

सदस्य

श्री सैम पित्रोदा (अध्यक्ष)

श्री पित्रोदा पिछले चार दशक से दूरसंचार के क्षेत्र में कार्यरत हैं। उन्होंने दूरसंचार को विकास और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया की गति तेज करने और संचार के मामले में दुनिया भर में मौजूद खाई को पाटने का साधन बनाकर उल्लेखनीय शुरूआत की है। उनकी पेशेवर जिंदगी उत्तरी अमरीका, एशिया और यूरोप के तीन महाद्वीपों में बंटी रही है। दूरसंचार को राष्ट्रीय विकास के एक साधन के रूप में इस्तेमाल करने के लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है।

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के सलाहकार के रूप में श्री सैम पित्रोदा ने भारत में दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी का बुनियादी ढांचा तैयार करने में मदद की। वह भारत में दूरसंचार आयोग के संस्थापक अध्यक्ष थे। वह पेयजल, साक्षरता, टीकाकरण, तिलहन और डेयरी से जुड़े राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी मिशनों के अध्यक्ष भी रहे। भारत की विकास संबंधी योजनाएं बनाने और नीतिगत दृष्टिकोण तय करने में उनका उल्लेखनीय योगदान है।

श्री पित्रोदा ने यूरोप और अमरीका में कई कंपनियां खोली और उनका संचालन किया। उनके नाम दुनिया भर में 75 से अधिक पेटेंट हैं।

डॉ. अशोक गांगुली

डॉ. गांगुली फर्स्ट सोर्स लिमिटेड तथा एबीवी प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष हैं और नवंबर, 2000 से भारत के रिजर्व बैंक के केन्द्रीय बोर्ड के निदेशक हैं। उनकी टेक्नोलाजी नेटवर्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नामक अपनी परामर्शी कंपनी है। संप्रति वे महिंद्रा एंड महिंद्रा, विप्रो लिमिटेड, टाटा एआईजी जीवन बीमा कंपनी लिमिटेड और आईसीआईसीआई ज्ञान पार्क के गैर–कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं।

डॉ. गांगुली व्यापार और उद्योग के बारे में प्रधानमंत्री की परिषद और निवेश आयोग के सदस्य हैं। डॉ. गांगुली 35 वर्ष से युनिलीवर पीएलसी/एनवी से इस पेशे से जुड़े रहे हैं। वे 1980 से 1990 तक हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड के अध्यक्ष और फिर 1990 से 1997 तक युनिलीवर बोर्ड के सदस्य के नाते दुनिया भर में अनुसंधान और टेक्नोलाजी की देखरेख करते रहे हैं।

वे भारत के प्रधानमंत्री की विज्ञान सलाहकार परिषद के सदस्य (1985–89) तथा अनुसंधान परिषदों के यूके सलाहकार बोर्ड (1991–94) के सदस्य रह चुके हैं। पद्मभूषण से सम्मानित तथा चीनी विज्ञान अकादमी के मानद प्रोफेसर के रूप में डॉ. गांगुली ने तीन पुस्तकें लिखी हैं ––*इंडस्ट्री एंड लिबरलाइजेशन, स्ट्रेटजिक मैन्युफैक्चरिंग फार कंपटीटिव एडवांटेज एंड बिजनेस ड्रिवेन आर एंड डी – मैनेजिंग नालेज टू क्रिएट वेल्थ।*

प्रो. पी. बलराम

प्रो. पी. बलराम मालीक्यूलर बायोफिजिक्स के प्रोफेसर हैं और संप्रति वे भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर के निदेशक हैं। इससे पूर्व वे इसी संस्थान में लेक्चरर (1973–77), सहायक प्रोफेसर (1977–82), सह–प्रोफेसर (1982–85), अध्यक्ष, मालीक्यूलर बायोफिजिक्स यूनिट (1995–2000) तथा अध्यक्ष, जैव–वैज्ञानिक विज्ञान प्रभाग (2002–05) रहे हैं। उनकी अनुसंधान की मुख्य रुचियां बायोआर्गेनिक केमेस्ट्री तथा मोलीक्यूलर बायोफिजिक्स रही हैं। वे 370 से अधिक अनुसंधान पत्रों के लेखक हैं। उन्होंने आईआईटी कानपुर से एम.एससी. की डिग्री (1969) तथा कारनेजी–मेलन, पिट्सबर्ग, यूएसए से रसायनशास्त्र में पीएच.डी. की डिग्री (1972) प्राप्त की है।

प्रोफेसर बलराम भारतीय विज्ञान अकादमी, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी तथा तृतीय विश्व विज्ञान अकादमी, ट्रिस्टी, इटली के फेलो हैं। प्रोफेसर बलराम को उनके कार्य की मान्यतास्वरूप अनेक पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए हैं जिनमें शांतिस्वरूप भटनागर पुरस्कार, सीएसआईआर (1986), अनुसंधान में उत्कृष्टता के लिए एलुम्नी पुरस्कार, भारतीय विज्ञान संस्थान (1991), रसायनशास्त्र में टीडब्ल्यूएएस पुरस्कार (1994), वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जी.डी. बिरला पुरस्कार (1994) तथा भारत सरकार द्वारा दिया गया पद्मश्री सम्मान (2002) शामिल है।

प्रोफेसर बलराम ने अनेक व्याख्यान दिए हैं और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय––दोनों स्तरों पर पत्रिकाओं के संपादकीय मंडल के सदस्य रहे हैं। संप्रति, भारत सरकार के अनेक समितियों के सदस्य हैं और केन्द्रीय मंत्रिमंडल की विज्ञान सलाहकार समिति, डीएई के न्यूक्लीयर साइंस में अनुसंधान बोर्ड, सीएसआईआर के सलाहकार बोर्ड तथा प्रधानमंत्री की वैज्ञानिक सलाहकार परिषद के सदस्य हैं। आप 10 वर्षों से अधिक समय तक 'करेंट साइंस' के संपादक रहे हैं।

डॉ. जयती घोष

डॉ. जयती घोष, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर इकॉनॉमिक स्टडीज एंड प्लानिंग, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज के अध्यक्ष और अर्थशास्त्र की प्रोफेसर हैं। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ाई की है। उन्होंने भूमंडलीकरण, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्त, विकासशील देशों में रोजगार पद्धतियां, मैक्रोइकॉनामिक नीति और लिंग तथा विकास से जुड़े मुद्दों पर शोध कार्य किया है।

उनकी प्रकाशित रचनाओं में *क्राइसेस एज ए कॉन्क्वेस्ट : लर्निंग फ्राम ईस्ट एशिया, द मार्केट दैट फेल्ड : ए डैकेड ऑफ नियोलिबरल इकॉनामिक रिफार्म्स इन इंडिया और वर्क एंड वैल बीइंग इन द एज ऑफ फाइनेंस* (प्रो. चन्द्रशेखर के साथ सह–लेखिका) शामिल हैं। वे पश्चिम बंगाल मानव विकास रिपोर्ट 2004 की मुख्य लेखिका थीं, जिसे विश्लेषण में उत्कृष्टता के लिए यूएनडीपी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने अनेक शोध पत्र भी लिखे हैं। तथा कई प्रमुख पत्र–पत्रिकाओं की नियमित स्तंभकार हैं।

डॉ. जयती घोष अनेक जनसूचना वेबसाइट्स के संचालन से जुड़ी हैं, इकॉनामिक रिसर्च फाउंडेशन की संस्थापक हैं और हेटरोडॉक्स डेवलपमेंट इकॉनामिस्ट्स के एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क इंटरनेशनल डेवलपमेंट इकॉनामिक्स एसोसिएट्स (आइडियाज) की कार्यकारी सचिव हैं। आप 2004 में आंध्र प्रदेश किसान कल्याण आयोग की अध्यक्ष रह चुकी हैं और अनेक प्रगतिशील संगठनों तथा सामाजिक आंदोलनों से करीब से जुड़ी हुई है।

डॉ. दीपक नय्यर

डॉ. दीपक नय्यर, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। वे ऑक्सफोर्ड और ससेक्स विश्वविद्यालयों तथा भारतीय प्रबंध संस्थान, कोलकाता में अध्यापन कर चुके हैं और 2000 से 2005 तक दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति रहे हैं। वे वाणिज्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार, भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार और वित्त मंत्रालय में सचिव रह चुके हैं।

दिल्ली विश्वविद्यालय में सेंट स्टीफंस कालेज के स्नातक डॉ. नय्यर रोडेस स्कालर बन गए और उन्होंने बल्लीओल कालेज, ऑक्सफोर्ड से अर्थशास्त्र मे डी.फिल. की उपाधि प्राप्त की। उन्हें अर्थशास्त्र में शोध में उल्लेखनीय योगदान के लिए वी.के. आर.वी. राव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनकी पुस्तकों में – *इंडियाज एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पालिसीज, द इंटेलिजेंट पर्सन्स गाइड टु लिब्रलाइजेशन, गवर्निंग ग्लोबलाइजेशन : इश्यूज एंड इंस्टीट्यूशंस और माइग्रेशन, रैमिटेनसेज एंड कैपिटल फ्लोज : द इंडियन एक्सपीरियंस* शामिल हैं।

डॉ. नय्यर बल्लीओल कालेज के मानद फैलो, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में क्वीन एलिजाबेथ हाउस, इंटरनेशनल डेवलपमेंट विभाग की सलाहकार परिषद के अध्यक्ष हैं। वे इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ युनिवर्सिटीज, पेरिस के उपाध्यक्ष और वर्ल्ड इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट इकॉनामिक्स रिसर्च, हेलसिंकी के संचालक मंडल के अध्यक्ष हैं। वे वर्ल्ड कमीशन आन द सोशल डाइमेंशन आफ ग्लोबलाइजेशन के सदस्य रह चुके हैं।

डॉ. नंदन नीलेकनी

इंफोसिस टेक्नोलाजीज लिमिटेड के संस्थापक सदस्य श्री नीलेकनी कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। इससे पहले वे इंफोसिस में प्रबंध निदेशक, अध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी रह चुके हैं।

श्री नीलेकनी भारत की नेशनल एसोसिएशन आफ साफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज (नेसकॉम) के संस्थापक सदस्य भी हैं। वे एक अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान और व्यापार सदस्यता संगठन द कांफ्रेंस बोर्ड, इंक के उपाध्यक्ष और लंदन बिजनेस स्कूल के एशिया प्रशांत क्षेत्रीय सलाहकार बोर्ड के सदस्य हैं। वे विद्युत क्षेत्र के लिए भारत सरकार के आईटी टास्क फोर्स के अध्यक्ष रह चुके हैं। वे भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की इनसाइडर ट्रेडिंग उपसमिति और कंपनी प्रशासन के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक के सलाहकार दल के सदस्य रह चुके हैं। वे जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन की समीक्षा समिति के सदस्य भी हैं और एक गैर–कार्यकारी सदस्य के रूप में रायटर बोर्ड में सेवा प्रदान करते हैं।

उन्होंने अनेक सम्मान प्राप्त किए हैं, जिनमें – फार्च्युन पत्रिका का *एशियाज बिजनेसमैन आफ द इयर* 2003 पुरस्कार (इंफोसिस के अध्यक्ष श्री एन.आर. नारायण मूर्ति के साथ) और एशिया बिजनेस लीडर अवार्ड्स (2004) में कारपोरेट सिटीजन ऑफ द इयर पुरस्कार और पद्मभूषण (2006) शामिल हैं। 2002 और 2003 में फाइनेंशियल टाइम्स और प्राइसवॉटरहाउस कूपर्स के विश्वव्यापी सर्वेक्षण के अनुसार उन्हें विश्व के सर्वाधिक सम्मानित बिजनेस लीडर्स में स्थान दिया गया। श्री नीलेकनी जनवरी, 2006 में लब्धप्रतिष्ठ विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) प्रतिष्ठान बोर्ड के 20 वैश्विक नेताओं में शामिल होने वाले सबसे युवा उद्यमी हैं।

डॉ. सुजाता रामदोराई

सुजाता रामदोराई स्कूल आफ मैथमेटिक्स, टाटा इंस्टीट्यूट आफ फंडामेंटल रिसर्च (टीआईएफआर) में प्रोफेसर हैं। वे विश्व में अनेक विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों में अतिथि प्रोफेसर रही हैं। संप्रति, चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट की अतिथि प्रोफेसर हैं।

डॉ. रामदोराई को शांतिस्वरूप भटनागर पुरस्कार के अलावा नार्वे ऐकेडमी आफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा आईसीटीपी श्रीनिवास रामानुजन पदक से सम्मानित किया जा चुका है। उनकी अनुसंधान की रुचियां अंकगणितीय संख्या सिद्धांत पर केन्द्रित हैं। साथ ही वे भारत में विशेष रूप से प्योर साइंसेज में शिक्षा और अनुसंधान से संबंधित मुद्दों के साथ जुड़ी रही हैं।

उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की पत्रिकाओं में अनेक शोध लेख लिखे हैं और अपने अनुसंधान कार्य में व्यापक रूप से सहयोग प्राप्त किया है। वे *साइक्लोटोमिक फील्ड्स एंड जेटावैल्यूज* की सह–लेखिका (प्रो. जे. कोर्स के साथ) रही हैं।

प्रविधि

- प्रमुख चिन्हित क्षेत्रों की पहचान
- विविध हितधारकों की पहचान और क्षेत्र में प्रमुख मुद्दों को समझना
- कार्य दलों का गठन तथा कार्यशालाओं/संगोष्ठियों का आयोजन करना, संबंधित विशेषज्ञों और हितधारकों के साथ विस्तृत औपचारिक और अनौपचारिक परामर्श करना
- प्रशासनिक मंत्रालयों और योजना आयोग के साथ परामर्श
- अध्यक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री को भेजे जाने वाले पत्र के रूप में सिफारिशों को अंतिम रूप देने के वास्ते एनकेसी में चर्चा
- प्रधानमंत्री को भेजे जाने वाले पत्र जिसमें सिफारिशें, प्रारंभिक उपाय तथा एनकेसी के संगत व्याख्यात्मक दस्तावेजों द्वारा समर्थित वित्तीय प्रभाव आदि शामिल हैं
- राज्य सरकारों, नागरिक समाज तथा अन्य हितधारियों के बीच सिफारिशों का प्रसार
- प्रधानमंत्री कार्यालय के तत्वावधान में सिफारिशों का कार्यान्वयन शुरू करना
- प्रस्तावों के कार्यान्वयन का समन्वय और अनुवर्ती कार्रवाई

कार्य दलः कार्यकारी समूहः पुस्तकालय, भाषा, कृषि, स्वास्थ्य सूचना नेटवर्क, अनु–स्नातक शिक्षा, चिकित्सीय शिक्षा, विधिक शिक्षा, प्रबंध शिक्षा, इंजीनियरी शिक्षा, परंपरागत स्वास्थ्य प्रणालियां, गणित और विज्ञान में और अधिक छात्र, मुक्त एवं दूरवर्ती शिक्षा

कार्यशालाएं/संगोष्ठियांः साक्षरता, अनुवाद, नेटवर्क, स्कूल शिक्षा, मुस्लिम शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, मुक्त और दूरस्थ शिक्षा, बौद्धिक संपदा अधिकार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कृषि, मुक्त शिक्षा संसाधन

सर्वेक्षणः नवाचार, स्वास्थ्य सूचना नेटवर्क, परंपरागत स्वास्थ्य प्रणाली और उद्यमिता

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग द्वारा अपनाई गई प्रविधि में शुरू में चिन्हित क्षेत्रों की पहचान की जाती है। यह चयन सरकार के भीतर और बाहर——दोनों स्तरों पर व्यापक परामर्श के आधार पर किया जाता है। इसके बाद इन क्षेत्रों में बहुविध हितधारकों की पहचान की जाती है और प्रमुख मुद्दे प्रकाश में लाए जाते हैं। यह मानते हुए कि सरकार, आयोग के कुछेक निधारित क्षेत्रों में पहले से ही पहल कर रही है, इसलिए क्षेत्रों का चयन आयोग द्वारा अनूठे मूल्यसंवर्द्धन के विश्लेषण को भी ध्यान में रखता है। यह काम या तो परंपरागत समस्याओं के लिए नवाचारी समाधानों की पेशकश करके अथवा किसी क्षेत्र में कार्यरत अलग–अलग समूहों को एक साथ लाकर किया जा सकता है।

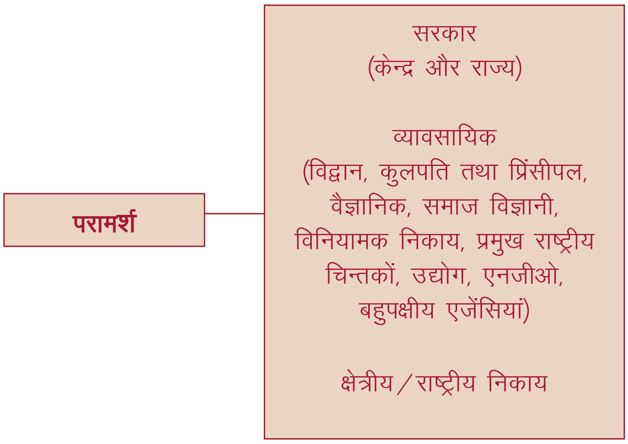

चिन्हित क्षेत्रों की पहचान के बाद विशेषज्ञों और व्यावसायिकों के कार्य समूहों का गठन किया जाता है। इन कार्य समूहों में विशिष्ट रूप से 5 से 10 विशेषज्ञ शामिल होते हैं और वे रिपोर्ट तैयार करने के लिए 3 से 4 महीने तक नियमित रूप से बैठकें आयोजित करते हैं। कार्य समूहों की रिपोर्टें, एनकेसी द्वारा अपनी सिफारिशें तैयार करने के वास्ते विचार–विमर्श के दौरान प्रयुक्त इन्पुटों में से एक इन्पुट होती हैं। इसके अलावा संबंधित विशेषज्ञों और हितधारकों के साथ अनौपचारिक परामर्श के साथ–साथ नियतकालिक आधार पर कार्यशालाएं और संगोष्ठियां आयोजित की जाती हैं जिससे कि यथासंभव एक व्यापक दृष्टिकोण प्राप्त किया जा सके। जिन मुद्दों के मामले में अनुभवों के एक अत्यंत व्यापक समझ की जरूरत होती है, उनमें सर्वेक्षण भी किया जा सकता है। एनकेसी ने विभिन्न ध्यातव्य क्षेत्रों के लिए अलग–अलग दृष्टिकोण अपनाए हैं, जिसका उद्देश्य एक ऐसी प्रक्रिया स्थापित करना है जो कि यथासंभव समावेशी और सहभागितापूर्ण हो। इस प्रक्रिया के माध्यम से एनकेसी विभिन्न मतों को एक साथ लाने वाले एक मंच के रूप में काम करता है जिससे कि मुद्दों को गहराई से समझा जा सके। विचार–विमर्श के इस स्तर पर संबंधित मंत्रालयों के प्रतिनिधियों को सक्रिय रूप से सहयोजित किया जाता है।

इस प्रक्रिया का पालन करते हुए आयोग के सदस्य सिफारिशों को अंतिम रूप देने के उद्देश्य से परामर्श तथा कार्य समूहों की रिपोर्टों में उठाए गए मुद्दों पर चर्चा करते हैं। चर्चाओं के कई दौरों के बाद प्रधानमंत्री को एक पत्र भेजा जाता है जिसमें प्रमुख सिफारिशें, प्राथमिक उपाय, संगत व्याख्यात्मक दस्तावेजों द्वारा समर्थित वित्तीय प्रभाव आदि भाामिल रहते हैं।

प्रधानमंत्री तथा संबंधित मंत्रालयों द्वारा सिफारिशें प्राप्त किए जाने के बाद राज्य सरकारों, सिविल समाज तथा अन्य हितधारियों के बीच एनकेसी की सिफारिशों का व्यापक प्रसार किया जाता है। सिफारिशों का कार्यान्वयन इसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय के तत्वावधान में विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ तालमेल और अनुवर्ती कार्रवाई सहित भाुरू किया जाता है।

2006 में प्रस्तुत की गई सिफारिशें

- पुस्तकालय
- अनुवाद
- अंग्रजी भाषा अध्यापन
- राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क
- शिक्षा का अधिकार
- व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण
- उच्चतर शिक्षा
- राष्ट्रीय विज्ञान और समाज विज्ञान प्रतिष्ठान
- ई–अधिकारिता

2007 में प्रस्तुत की गई सिफारिशें

- स्वास्थ्य सूचना नेटवर्क
- पोर्टल
- मुक्त शैक्षिक पाठ्यविवरण
- विधिक शिक्षा
- चिकित्सीय शिक्षा
- प्रबंध शिक्षा
- मुक्त और दूरस्थ शिक्षा
- बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर)
- नवाचार
- परंपरागत स्वास्थ्य प्रणाली
- सरकारी वित्तपोषित अनुसंधान के लिए विधिक तंत्र

जारी कार्य

- पोर्टल (जैवविविधता तथा शिक्षक प्रशिक्षण)
- स्कूल शिक्षा, मुस्लिम शिक्षा और साक्षरता
- इंजीनियरिंग शिक्षा
- विज्ञान और गणित में और अधिक छात्र
- और अधिक पीएच.डी.
- उद्यमता
- कृषि

संभावित भावी क्षेत्र

(विचारार्थ)

- छोटे और मझोले उद्यमों की ज्ञान जरूरतें
- सरकारी प्रक्रिया पुनः इंजीनियरी